SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: They should understand the feelings of other regions also.. .*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Shankar Dayal Singhji, please sit down.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Not a nay a paisa is being spent by the Central Government... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN; You can mention it at twelve o'clock. Otherwise, you will not go on record.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI:*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Virumbi. please sit down. The questions are tabled by you people, not by me. So. it is in your interest to ask questions. The Ministers are here. After twelve o'clock we will discuss about it- I am thankful to you for being quiet now.

Question No. 641

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की हल्दिया इकाई

***641. श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री 24 फरवरी, 1994 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 52 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड का हल्दिया में स्थित उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया था और इसमें वर्ष 1979 में कितने कर्मचारी भर्ती किये गये थे ;

(ख) इस कारखाने में वर्ष 1978 से प्रतिवर्ष कितना उर्वरक उत्पादन किया जा रहा है ;

(ग) 31 मार्च, 1992 तक इस कारखाने पर मद-वार कुल व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 1970 से इस कारखाने के सुधार पर निरन्तर व्यय किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरियो) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) हल्दिया स्थित उर्वरक परियोजना सरकार द्वारा, नवम्बर, 1971 में मंजूर की गई थी । इसे 1979 में यांत्रिक रूप से पूरा किया गया था । वर्ष 1979 में इस परियोजना के लिये 172 कर्मचारियों की भर्ती की गयी थी ।

(ख) आरम्भण के दौरान उपस्कर की बार-बार खराबियों के कारण आरम्भण कार्यकलाप अक्तूबर, 1986 में स्थगित कर दिये गये थे । आरम्भण कार्यकलापों के दौरान उत्पादित उर्वरकों की थोड़ी सी मात्रा के सिवाय, इस परियोजना में कोई उत्पादन नहीं हुआ ।

(ग) 31-3-1992 तक इस परियोजना पर किये गये व्यय के ब्यौरे विवरण-I में दिये गये हैं । (नीचे देखिये)

(घ) परियोजना का निर्माण अक्तूबर, 1979 में पूरा हुआ था । राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पावर आपूर्ति करने की असमर्थता के कारण, आरंभण कार्य में दो वर्ष का विलंब हुआ । आरंभण कार्य कलाप 1982 के आरंभ में शुरू हुये । अक्तूबर, 1986 में आरंभण कार्य के स्थगन तक, इस परियोजना पर 477.54 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी थी । तत्पश्चात 1.25 करोड़ रु0 प्रति मास की दर से केवल स्थायी प्रभार ही खर्च किये गये जिन्हें 1-4-1989 से बढ़ाकर 1.52 करोड़ रु0 प्रति माह कर दिया गया ।

*Not recorded.

विवरण-I

31-3-1992 तक हल्दिया परियोजना पर व्यय किए गए खर्च के ब्यौरे

(रु० करोड़ों में)

क्र.सं.	मद का नाम	व्यय (31-3-1992तक)
1.	मुख्य संयंत्र	127.06
2.	उपयोगिता संयंत्र	40.06
3.	माल, संचालन, भंडारण तथा बेगिंग	17.24
4.	भंडार, कार्यशाला तथा गैर संयंत्र भवन	1.56
5.	यार्ड पाईपिंग	3.33
6.	अनुषंगी सेवायें तथा अन्य सामान्य सुविधायें	3.11
7.	परिवहन तथा रेलवे साइडिंग	2.14
8.	भूमि विकास और बाह्य सेवायें	2.95
9.	मिट्टी हटाना और निर्माण उपस्कर	0.87
10.	कालोनी, सार्वजनिक भवन, प्रशिक्षण केन्द्र तथा विद्यालय भवन	9.47
11.	अतिरिक्त पुर्जे	2.25
12.	प्रवासी कार्मिकों पर आय कर तथा मुख्यालय व्यय	2.09
13.	विभागीय प्रभार	156.43
14.	आरंभिक कार्यकारी पूंजी	0.23
15.	फुटकर व्यय	1.30
16.	परीक्षण और आरंभण	115.74
17.	वित्त प्रबंध प्रभार	220.69
18.	आस्थगित राजस्व व्यय	3.82
19.	आरंभण अवधि के दौरान उत्पादों की बिक्री के लिये ऋण	(-)21.72
	योग :	688.62

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : उप-सभापति महोदया, 477.54 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद सन् 1986 में शासन को यह महसूस हुआ कि यह कारखाना क्षमता के साथ और गति के साथ नहीं चल सकता तब उसको बंद करने का निर्णय लिया, तो कारखानें का काम बंद करने का निर्णय लेने के बाद उस समय कितने श्रमिक और कर्मचारी कार्यरत थे और वे कब तक कार्यरत रहे तथा वर्तमान में कितने श्रमिक और कर्मचारी कार्यरत हैं और उन पर कितना व्यय किया जा रहा है, इसका उत्तर मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं ?

SHRI EDUARDO FALEIRO; Madam, I have given all these figures in the Annexure. The number of employees is also mentioned in the main part of the answer. So, that is the position. But as far as the question is concerned, we have discussed it in the House in the course of this Session itself. It was said that we could not even commission this project.

SHRI VIREN J. SHAH: You could have taken an immediate decision.

SHRI EDUARDO FALEIRO: it is very difficult to decide as to what is to be done. If you take it in a simplistic manner, one would have said it is purely an economic thing and yon close it down. But then one has to look at the labour, one has to look at the needs of the region in. terms of fertilisers. One has to explore all possibilities.

SHRI VIREN J. SHAH: If this could not be commissioned, give pension to labour and close it down.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Have I identified yon, please? Yon are a very senior Member.

SHRI EDUARDO FALEIRO: If we take that view, which strikes at ' least in my mind, if not in my heart, that it is a project that cannot be commissioned, then the logical thing would be to dose it doom and give pension to

[Shri Eduardo Faleiro}

the labour. But then, there are other broader implications. One has to look at these things, viz. in terms of the requirements of fertilizer of that area, in terms of such a beautiful location by the side of Haldia pott having all facilities. So, it is difficult 1.0 take a decisjon. And the decision can only b,e to explore all possibilities for having a fertiliser plant there

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : उपसभापति महोदया, मेरा एक प्रश्न जो इस प्रश्न में था कि अभी तक कितने कर्मचारी या मजदूर वहां काम कर रहे हैं, इसकी संख्या मंत्री जी बतायें ?

SHRI EDUARDO FALEIRO: He has asked this question and I have given the number here saying so many employees were employed. On this and on any other point, if any further information is required, I will give it to the hon. Member immediately after the Question Hour if he can spare a few minutes and drops in my room in Parliament House.

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : अभी मेरा दूसरा प्रश्न है।

उपसभापति : आपके दो हो गए।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : नहीं जी, वह तो मैंने पहला ही किया था।

उपसभापति : पहले वह सब डिटेल आप उनको दे दीजिए।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : अब दूसरा मैं कर रहा हूं।

उपसभापति : आप एक ही वक्त में एक पूछ लिया कीजिए, दो न कीजिए।

श्री शिव प्रसाद चनपुरिया : मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बताया गया है कि 31-3-92 तक 688.61 करोड़ रुपए व्यय हुए जबकि इस बार के बजट में 1994-95 में उल्लेख है कि 31-3-93 तक 751.09 करोड़ राशि व्यय हुए हैं। तो इतनी विशाल राशि व्यय करने के बाद भी कारखाने में कुछ उत्पादन नहीं किया जा सका। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न है कि क्या परियोजना त्यागी नहीं जा सकती है क्या उसे चालू न कर पाने की परिस्थितियों के लिए उसके दायित्व उसकी जांच हेतु शासन संसदीय समिति का गठन करेगा ?

SHRI EDUARDO FALEIRO: No. As on date there are 1,547 employees in position in Haldia. Since the introduction of 'ha Voluntary Retirement Scheme, 192 employees, have opted for the same till date and 250 employees have been shifted out to other units. Now, as far as the question whether we will investigate and how this project failed anj failed badiy is concerned, we will look into it.

श्री वीरेन्द्र कटारिया : शुक्रिया मैडम डिप्टी-चेयरमैन। मैडम, फर्टीलाइजर चाहे वह यूरिया हो या डी.ए.पी. हो, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और इस पर बहुत कीमती फारेन-एक्सचेंज खर्च हो रहा है और दूसरी ओर हमारे जो प्रिस्टीजियस फर्टीलायजर प्लांट्स हैं, चाहे वह हल्दिया का है या सिन्द्री का है, पारादीप फॉस्फेट और भी कई प्लांट्स हैं जोकि सिक पड़े हैं। महोदया, फिर यह बीमारी भी बड़ी अजीब है। हल्दिया का प्लांट लगाया और इसमें कई अड़चनें आईं और जब उसको चलाने की कोशिश हुई तो उसकी मशीनरी का ब्रेक-डाउन हो गया और आज तक दस साल से ऊपर का अरसा हो गया है, वह प्लांट चल ही नहीं पाया है। फिर सरकार ने 1986 में इस यूनिट की कमीशनिंग एक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हिंदुस्तान फर्टीलायजर का हल्दिया यूनिट और एफ.सी.आई. के यूनिट सिक पड़े हैं और अकेले हल्दिया यूनिट में करोड़ों रुपया बगैर किसी काम के तनख्वाह की शक्ल में दिए जाते हैं ? मैडम, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जो सिक यूनिट्स हैं, उनमें एक टैक्नोलोजी के बजाय कई मुल्कों की, कई किस्म की टैक्नोलोजी इस्तेमाल की गई

है जिसकी वजह मे प्राब्लम्स पैदा हुई हैं और इसके अलावा जो वर्ककल्चर है, वह भी इस सिकनेस की बहुत बड़ी वजह है।

उपसभापति : कटारिया जी, आप एक सवाल पूछ लीजिए, वजूहात वह बता देंगे।

श्री वीरेन्द्र कटारिया : मैडम, क्या यह सही है कि जिस प्लांट में एक ही टैक्नोलोजी का इस्तेमाल किया गया है, वह प्लांट्स जैसे "इफ्को" और कृफ्को"" के हैं, वह एफीसिएंट तौर पर चल रहे हैं, लेकिन जो सिक यूनिट्स हैं उसकी वजह उनमें वर्क-कल्चर और कई किस्म की टैक्नोलोजी का इस्तेमाल है।

THE DEPUTY CHAIRMAN; Mr. Katariaji, it is not a special mention. It is a Question Hour. Please put the question.

SHRI VIRENDRA KATARIA: I would like to know whether it is a fact that these plants have become sicfc because many technologies from many countries have been used in these plants. This is one reason. The second reason is that work culture has gong *in* low that these plants have be-ccrre sick. I would like to know from th- Minister whether it is correct. If it is correct, what is the Government gajrig to do lo se? the things right? Thir is part (a) of my supplementary.

श्री शंकर दयाल सिंह : मैडम, इसके पहले कि इस सवाल का जवाब हो, मैं जानना चाहता हूं कि आज प्रधान मंत्री का दिन है...

THE DEPUTY CHAIRMAN; Please sit down. That is enough.

अभी नहीं आप बैठिए शंकर दयाल जी।

I *am* not allowing.

SIJRI M. A. BABY: If the Prime Minister had written to you that there is some legitimate reason, then', it. is understandable.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the Prime Minister has written that there is a reason. That is why he has not come. Other Ministers are here who are competent enough to answer. So, please don't insist upon the presence of the Prime Minister. वह शाम को आयेंगे

SHRI M. A. BABY: Has he taken your permission?

THE DEPUTY CHIARMAN: Yes, he has taken my permission.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Madam Deputy Chairman, both the reasons given by ths honourable Member are among the reasons which have led to the sick-nsss. In fact, there are two reasons fn- non commissioning of Haldia plant-Number one, there was a mismatch of technology. In fact, 13 credits from 8 countries were obtained. The approach of our fertilizer industry in the initial stages was in a mannei of speaking. that, we were looking at more to the credii first than to the machinery whether they could supply. Therefore,, the surveys were not so accurate as they are today. We have learnt. our les-' sons today. Therefore, both in the contort of a lot of technologies involved and mismatch of technologic; and lack of chick on technology before importing is another reasons.

Then, I must also admit here with a .irsat deal of regret that industrial relations have not been so good. The work culture has not been the best. These are definitely among the reasons.

Mow what we hav; dons is that we havg already put this before—as we must—the BIFR. The BIFR in turn has appointed ICICI which is an organisation to look, number one, whether revival was possible; and numfeef two, if so. they should submit a plan for revival.

श्री वीरेन्द्र कटारिया : मैडम, मैं जानना चाहता हूं कि इस प्लांट को शुरू करने में कितना पैसा लगेगा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ?

उपसभापति : आपका सवाल हो गया।

You have put your question. When you frame a question, please everything ;in a very concise form. I will get the answer. If you put a lengthy ques tion, then, the time of the House will be taken away. Next time we will do it.

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभापति महोदया, पूर्वी क्षेत्र के लिए, ईस्टर्न रीजन के लिए एक असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। न सिर्फ हल्दिया बल्कि नामरूप, बारौनी, सिंदरी, गोरखपुर और दुर्गापुर, सब के सब फर्टिलाइजर प्लांट बंद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने अखबारों में यह पाया कि प्रधान मंत्री ने तीन कैबिनेट मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है ताकि स सवाल पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। अगर यह सच है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब तक इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले लिया जाएगा ?

SHRI EDUARDO FALEIRO: It is true that both the HFC and the FCI have not been functioning ever in expected capacity. The utilisation in their case has been around 25-30 per cent and they have been really going into financial difficulties from the very beginning. Now both the companies are before the BIFR. The BIFR, the Government and the agencies involved! have to take a comprehensive view of he companies and not just of the plants.

SHRI CHATURANAN MISHRA: My aint is the Prime Minister has set up a committee of Cabinet Members to settle this issue and the BIFR is suspended for the time being. The Committee will find a way out of the problem. Is that true? If it is true, I want to know from you whether it is rime-bound.

SHRI EDUARDO FALEIRO: There is a Committee constituted recently under the chairmanship of the Finance Minister. The Deputy Chairman of the Planning Commission and also the Minister concerned are there. They will look not only into these companies but also into the whole public sector, wherever there is the problem of sickness and things of that sort. But that cfoes not override the BIFR at aM. The BIFR continues with its own work-*(Interruption).*

SHRI CHATURANAN MISHRA:. I just want to know whether there is any lime limit fixed.

SHRI EDUARDO FALEIRO: It has 10 be fixed by the BIFR.

श्री जनार्दन यादव : मैडम, मैं आपके माध्यम मे मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हल्दिया जो कारखाना है खाद का, 751 करोड़ रुपया इस पर लागत लग चुका है और वह हमेशा सिक ही रहता है। उसी प्रकार से बारौनी भी बंद है, सिंदरी भी बन्द है। तो क्या मंत्री महोदय, हिन्दुस्तान में खाद के कारखाने बन्द करके विदेशी कंपनियों के माध्यम से खाद लाकर हिन्दुस्तान के किसानों को देना चाहते हैं या जो सिक करखाने हैं उस पर अधिक पूंजी लगाकर सस्ते दर पर किसानों को खाद देना चाहते हैं ?

SHRI EDUARDO FALEIRO; We are taking and we will take all the steps to revive, if possible, these companies. That is why time is taken. We could have closed down these companies also. But we want these companies to continue. We want to do whatever revamping could be done to them as fertiliser companies- We are working on that. But it is not an easy thing to do. We have to take the workers into confidence; we have to take the officers into confidents: We have to take the officers into confidence; we have to take the banks into confidence; we have also to take the differen State Governments involved into confidence. We have to reach an agreement and that agreement has not been visible.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, let us first put the record straight. Haldia is not only a fertiliser plant. It is a fertiliser and chemical complex. Only some small figures are given. About 41,000 tonnes of fertilisers and 17,000 tonnes of chemicals were produced in this factory.

My question to the hon. Minister is whether he is aware that about eight Committees were formed since 1986 to find out the real causes and how to recommission the plant. I repeat it. In 1986, it was closed down so that it could be recommissioned without any problem. Eighth Committees were formed; one Committee per year or, perhaps, more than that. An apple a day makes a man healthy, but a Committee a year could not make Haldia healthy. Is it a. fact that in July 1989, the Cabinet had approved, in principle, the recom-missioning of the Haldia plant, as per she report of the German consultants Lidey, with a Rs. 123 crore investment, for producing nitro-phosphates with imported ammonia and phosporic acid? If so, what happened to that proposal?

SHRI EDUARDO FALEIRO; Several Committees have been[1] appointed. I do not have their exact number with me. I do not have the details of the proposals of the consultants-

THE DEPUTY CHAIRMAN: Give them to him.

SHRI EDUARDO FALEIRO; I can give the hon. Member all the details on this matter. It is not just a matter of answering a question in Parliament. *(Interruption).*

SHRI MD. SALIM: You should have come prepared. It is a specific question.

SHRI EDUARDO FALEIDO: I will reply to everything *{Interrup-tions).* I have just today fixed a meeting with Dr. Biplab Dasgupta which is to be after the Question Hour today on this issue. I want to go into all the facts. There is the interest of the Government. It is not just giving some reply to a question in Parliament. It is a matter of finding a solution to the problem. Therefore, any Member is welcome to have discussion. The point involved is that Udey gave a report. Now, the report involved a substantial amount of money. I am unable to confirm the enact amount because I don't have the details. But I remember that It did involve a substantial technological upgradation. It wag not in our view a long term solution and the main thing is that the price of fertilizer which we produce, the retention price, would be substantially above the norm, and, therefore, for every tonne of fertilizer produced, some loss would be incurred though the purpose of this company is that this should make profit or at least should meet the cost, but on every tonne of fertilizer produced, loss would be made. Therefore, that proposal was not accepted. As I have said earlier, immediately after the Question Hour today. I can go into this question in great detail in *mv* room.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, मैं आपने जो बजट प्रपोजल की बुकलैट 1994–95 की ईश्यू की है, उसमें से क्वोट करके पूछना चाहता हूं :–

"Meanwhile, as per the recently amended Sick Industrial Companies (Special Provision) Act, 1985, the Com pan$_v$ the Hindustan Fertilizer Corpora tion Limited, has made a reference to. the Board for Industial and Financial Reconstruction (BIFR) in regard to its furture operations. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dave, you should not read out any paper. *(Interruptions)* Please don't read out papers during the Question Hour. You put your question. The Minister must be knowing it. I won't allow it. *(Interruption).*

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE.- The BIFR in their first meeting on 12th November, 1992 have declared HFC as a sick company. *{Interruptions)* *

THE DEPUTY CHAIRMAN; It is not going on record.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:*

THE DEPUTY CHAIRMAN: You should not read out any papers. *(Inter ruptions)*

*Not recorded.

श्री अनन्तराव देवशंकर दवे : मैं उसी बजट प्रपोजल पर. . .

उपसभापति : ठीक है, उनको मालूम होना चाहिए ।

श्री अनन्तराव देवशंकर दवे : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो रिवाइवल पैकेज भेजना था, वह भेजा है या नहीं और अगर नहीं भेजा तो आपने क्यों नहीं भेजा ?

SHRI EDUARDO FALEIRO: I have already mentioned that the ICICI has to work for the revival of the project. We will support this with our suggestions and in every possible manner. We will follow all these instructions and directions of the BIFR to see that viable projects come up in that region.

फलदार पेड़ उगाने के लिये वन भूमि का आबंटन

*542. **श्री अजीत जोगी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास पर 30,000 करोड़ रुपए व्यय करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में तीन करोड़ परिवारों को फलदार पेड़ उगाने के लिए बन भूमि आबंटित करके उन्हें रोजगार दिलाने हेतु उपरोक्त राशि में से 12,000 करोड़ रुपए का आबंटन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त धनराशि में से आन्ध्र प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है और इससे कितने ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचेगा ?

*Not recorded.

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30,000 करोड़ रु० के आबंटन का सुझाव दिया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक आबंटन निम्न प्रकार रहा है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	आबंटन
1992—93	3600
1993—94	5010
1994—95	7010

(ख) जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अजीत जोगी : उपसभापति महोदया, यह बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण विकास के नाम पर 30,000 करोड़ रुपए 8वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय शासन द्वारा व्यय किए जायेंगे, पर यह उतनी ही निराशाजनक बात है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत जो राशि खर्च हो रही है, उसमें से कोई भी राशि वन-विभाग की रिजर्व और प्रोटेक्टिव भूमि पर वृक्षारोपण के नाम पर, विशेषकर फलदार [illegible] करने वाले वृक्षों के नाम पर खर्च नहीं की जाएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि, वे भी उस वर्ग से आते हैं, जिस वर्ग से मैं आता हूं, ग्रामीण विकास का कार्यक्रम जिस तरह से मैदानी इलाकों में लागू किया जा रहा है, उसी तरह से अगर आदिवासी इलाकों में भी लागू किया जाएगा, वैसे ही कार्य वहां भी लागू किए जायेंगे तो उसका फायदा अनसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिलेगा, वहां आपको ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो कार्य वहां के लोगों, वहां के [illegible] और [illegible] के [illegible] हों। आदिवासी का [illegible] सीधा जल, जमीन और जंगल से